

बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं

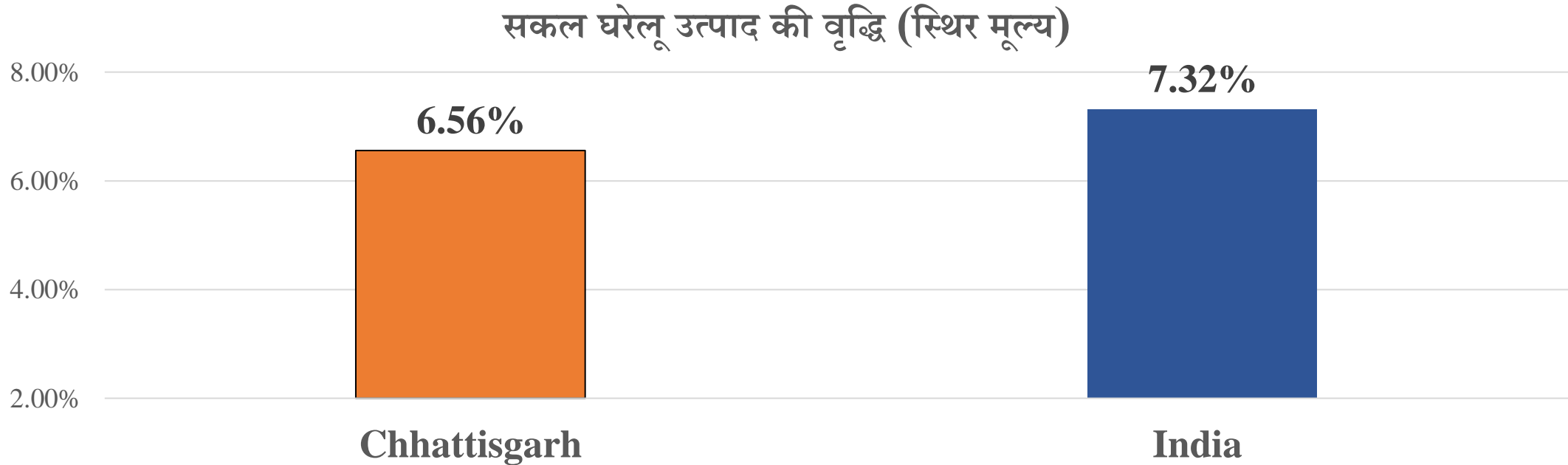


छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग



आर्थिक स्थिति - जीएसडीपी वृद्धि (FY 2023-24)

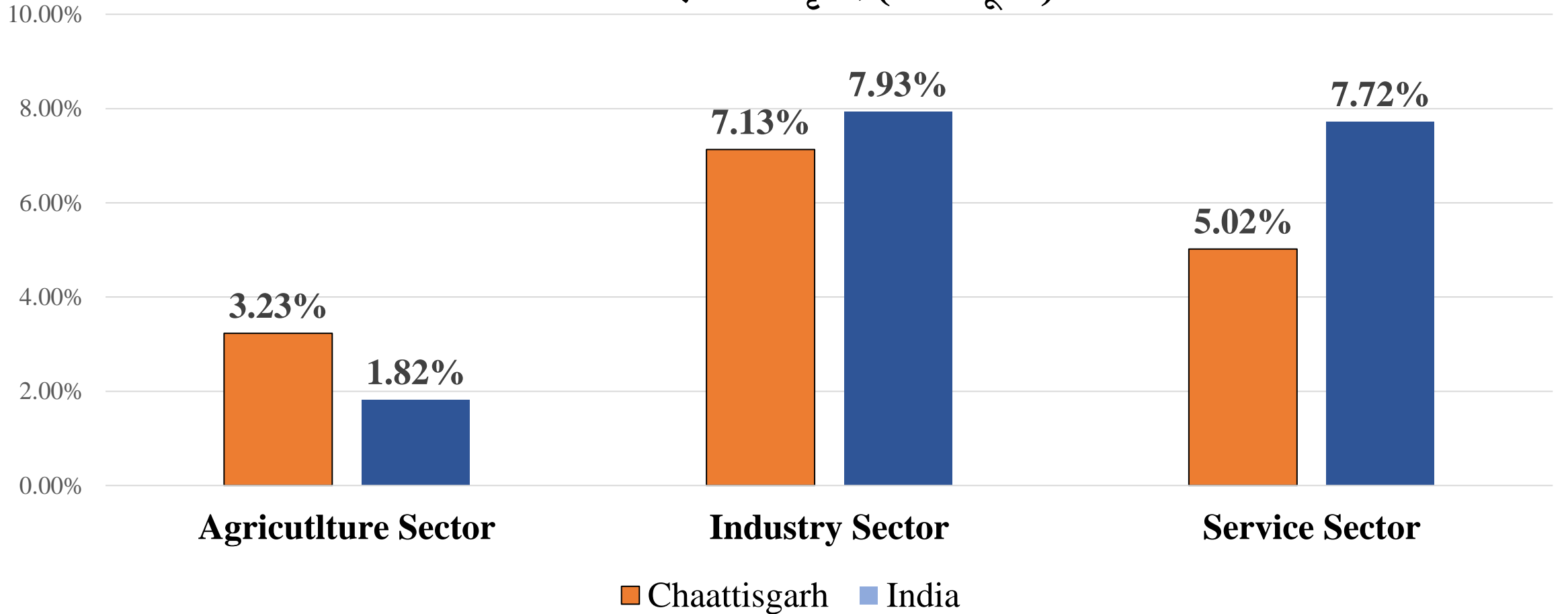
- वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी (स्थिर मूल्य पर) 3,02,118 करोड़ से वित्त वर्ष 2023-24 में रु. 3,21,945 करोड़ होने का अनुमान है, जो कि **6.56%** की वृद्धि है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी वृद्धि (प्रचलित मूल्य पर) **8.93%** दर के साथ रु.5,05,887 करोड़ होने का अनुमान है।





आर्थिक स्थिति-क्षेत्रीय वृद्धि (FY 2023-24)

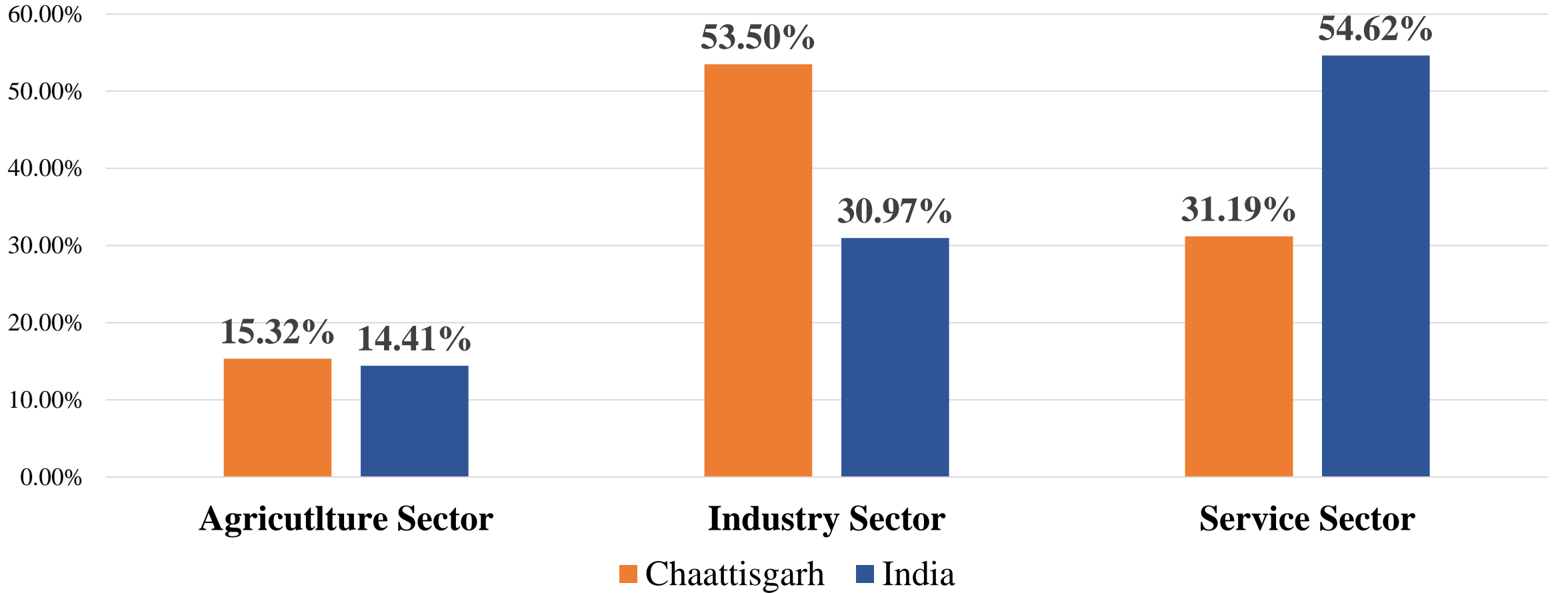
क्षेत्रवार जीएसडीपी वृद्धि (स्थिर मूल्य)





आर्थिक स्थिति - क्षेत्रीय योगदान

क्षेत्रीय योगदान (वित्तीय वर्ष 2023-24)

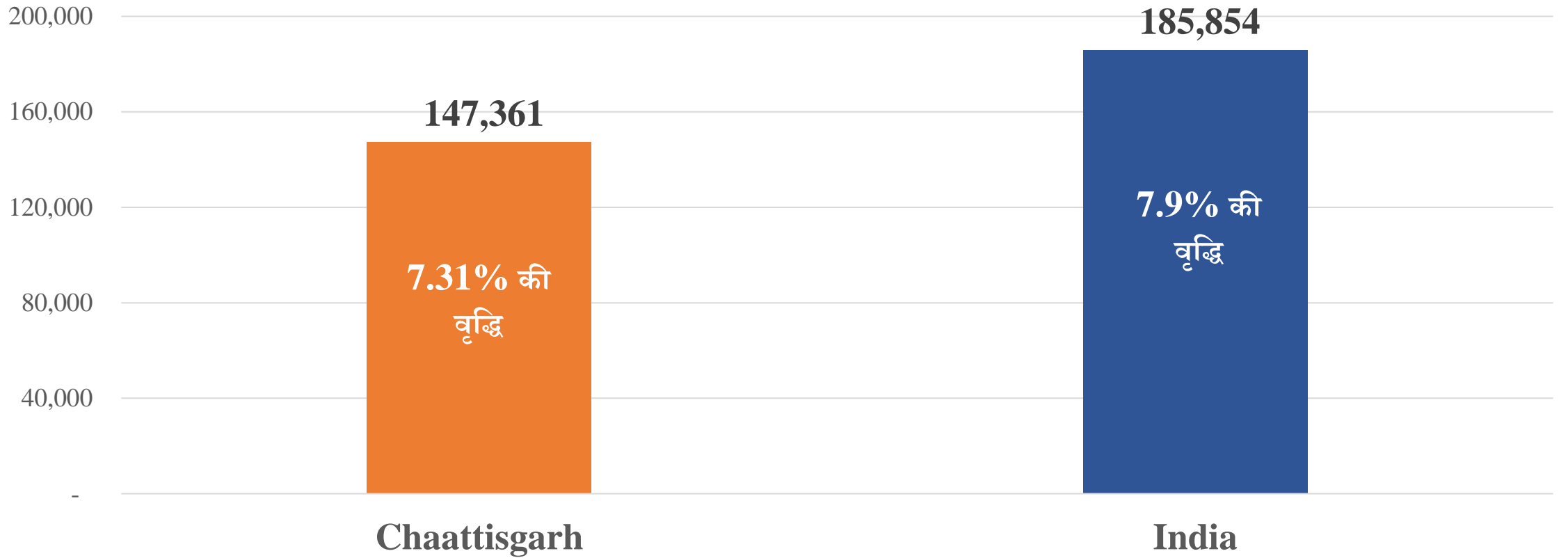




आर्थिक स्थिति

(रुपये में)

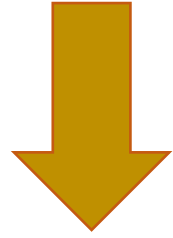
प्रति व्यक्ति आय (वित्त वर्ष 2023-24)



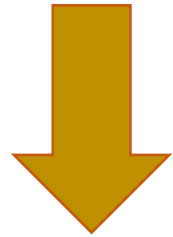


विकसित छत्तीसगढ़ रोडमैप

अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विज्ञान@2047



2028 तक जीएसडीपी 10 लाख करोड़



10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ





10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ

1. **GYAN** : हमारे आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु
2. तकनीक आधारित रिफार्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास
3. तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना
4. प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल
5. अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नयी संभावनाओं पर जोर
6. सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना
7. बस्तर-सरगुजा की ओर भी देखो
8. डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पाकेट्स
9. छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास
10. क्रियान्वयन का महत्व



मोदी की गारंटी

- **प्रधानमंत्री आवास योजना** के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान। वर्ष 2023-24 द्वितीय अनुपूरक में 3,799 करोड़ रुपये।
- महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में **महतारी वंदन योजना** के तहत प्रति वर्ष 12,000 रुपये सहायता का प्रावधान।
- **कृषक उन्नति योजना** के तहत 10,000 करोड़ रुपये इससे 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 02 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे।



मोदी की गारंटी

- ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए **जल जीवन मिशन** के तहत 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- **तेंदूपत्ता संग्राहकों** को गत वर्ष 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर **5,500 रु प्रति मानक बोरा भुगतान**
- **दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना** के तहत भूमिहीन मजदूरों को गत वर्ष 7000 प्रति वर्ष से **बढ़ाकर 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान** के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान ।



मोदी की गारंटी

- प्रदेशवासियों के लिए **श्री रामलला दर्शन** के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए **छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना** के क्रियान्वयन का प्रावधान ।
- **राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर)** के विकास हेतु विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान ।



मोदी की गारंटी

- **इन्वेस्ट छत्तीसगढ़** के आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- **राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास** की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान ।



राजकोषीय स्थिति

- इस वर्ष के बजट में कोई नया कर नहीं होने के बावजूद पिछले वर्ष के अनुमान की तुलना में राज्य का अपना राजस्व 22% बढ़ने का अनुमान है ।
- राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा रु. 16,296 करोड़ होने का अनुमान है जो जीएसडीपी का 2.90% है ।



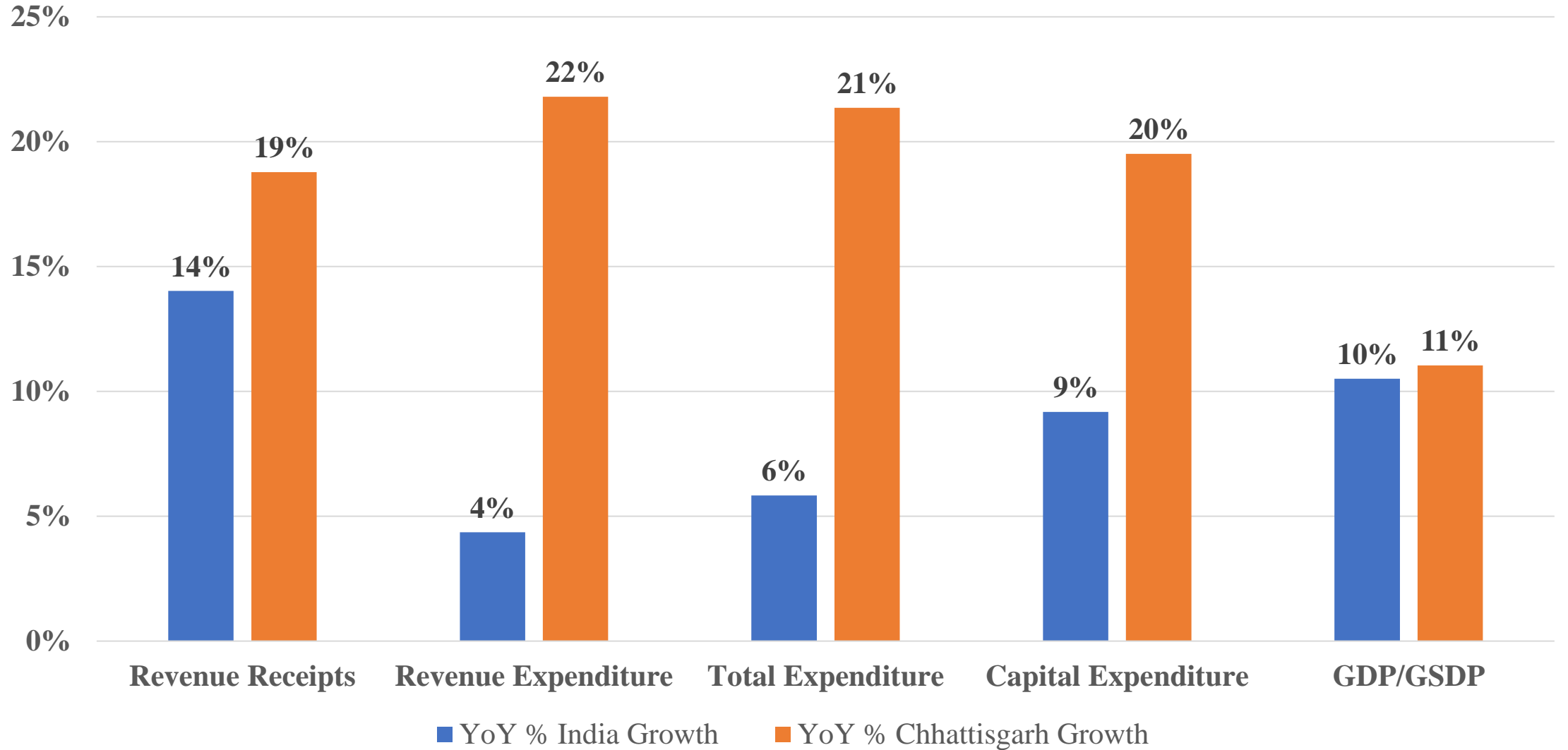
राजकोषीय स्थिति

□ वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व आधिक्य 1,060 करोड़ रुपये अनुमानित है।

□ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का पूंजीगत व्यय 22,300 करोड़ अनुमानित है। जो कुल बजट का 15% और पिछले वर्ष के बजट से 20% अधिक है। यह पिछले 5 वर्षों के औसत पूंजी व्यय से 12% अधिक है।



राजकोषीय स्थिति

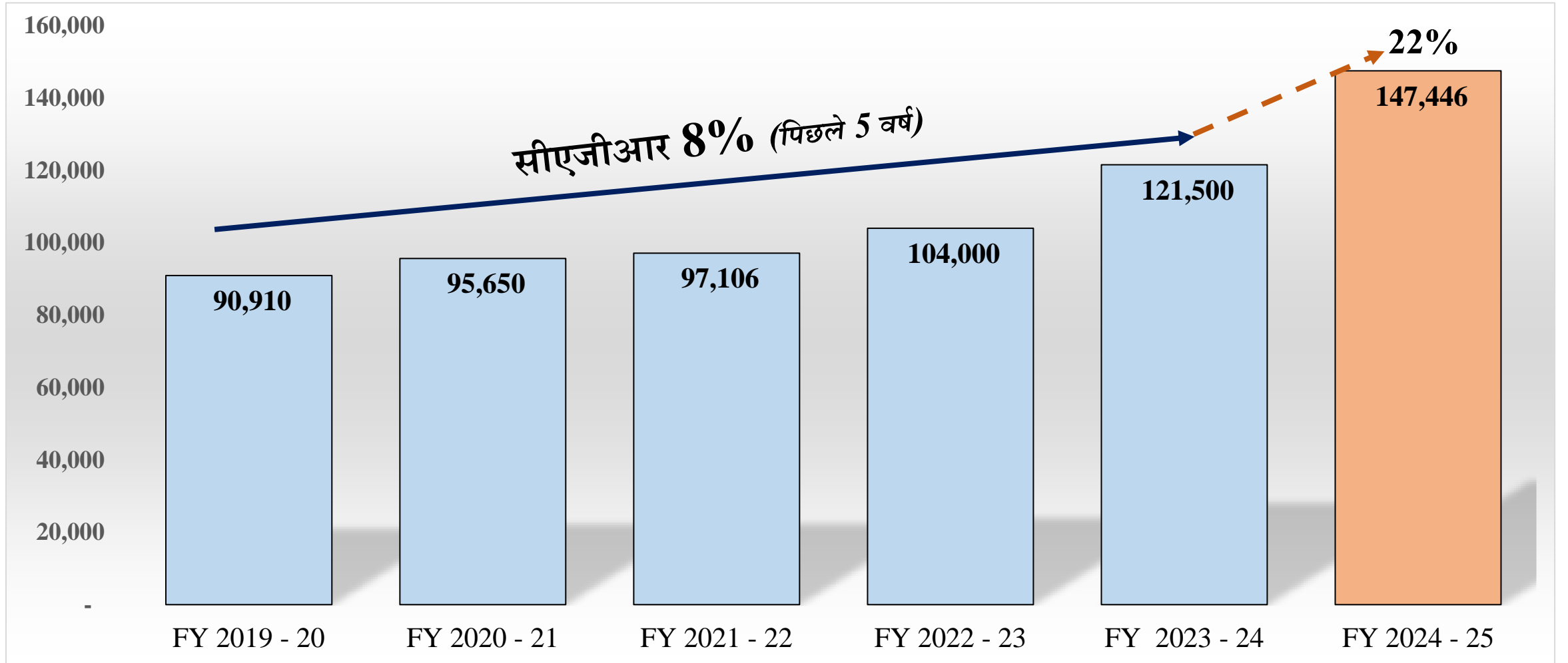




बजट अनुमान और साल- दर-साल वृद्धि



(करों में)





बजट एक नजर में



(करोड़ों में)

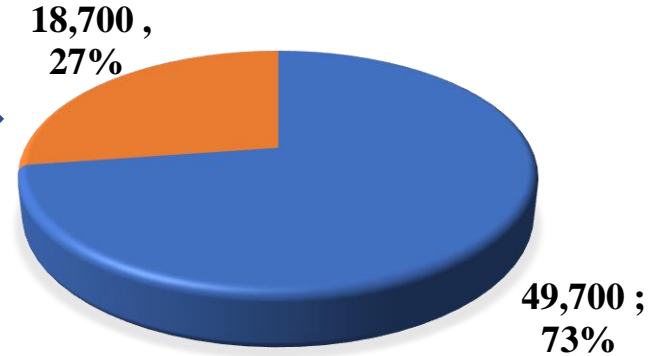
क्र.सं.	विवरण	बजट अनुमान 2023-24	बजट अनुमान 2024-25	विकास %
1.	कुल आय	1,21,501	1,47,500	22%
2.	कुल व्यय	1,21,500	1,47,446	22%
3.	राजस्व व्यय	1,02,501	1,24,840	22%
4.	पूंजीगत व्यय	18,660	22,300	20%
5.	राजस्व आधिक्य	+3,500	+1,060	-
6.	राजकोषीय घाटा	-15,200	-16,296	-
7.	जीएसडीपी	5,05,887 (अ)	5,61,736*	11%
8.	जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा %	-2.99%	-2.90%	-



वित्त वर्ष 2024 - 25: प्राप्तियाँ

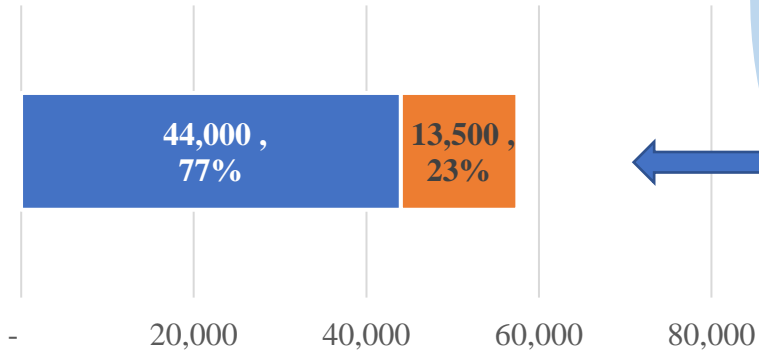
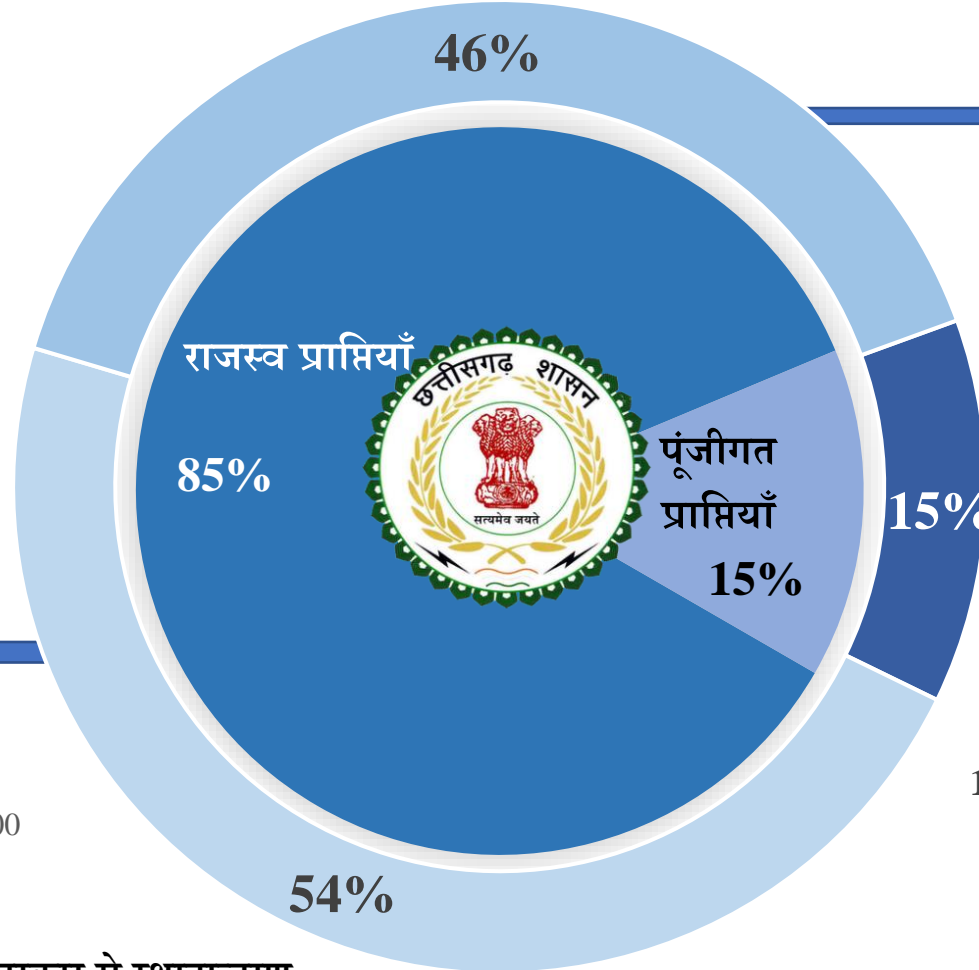
(करोड़ों में)

राज्य का अपना राजस्व (SOR)
राजस्व प्राप्तियों का 46%



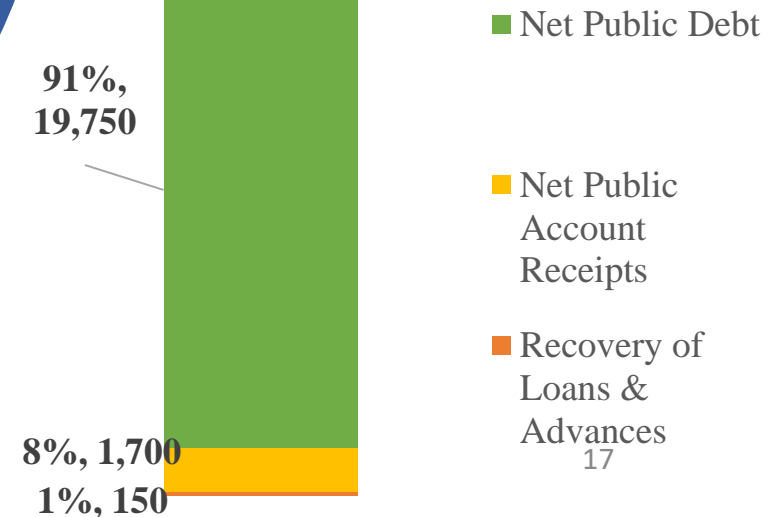
■ State Own Tax Revenue
■ State Own Non-Tax Revenue

	INR करोड़	%
आय प्राप्तियाँ	1,25,900	85%
पूंजीगत प्राप्तियाँ	21,600	15%
कुल प्राप्तियाँ	1,47,500	



■ Share of Net Proceeds of Union Taxes
■ Grants from GoI

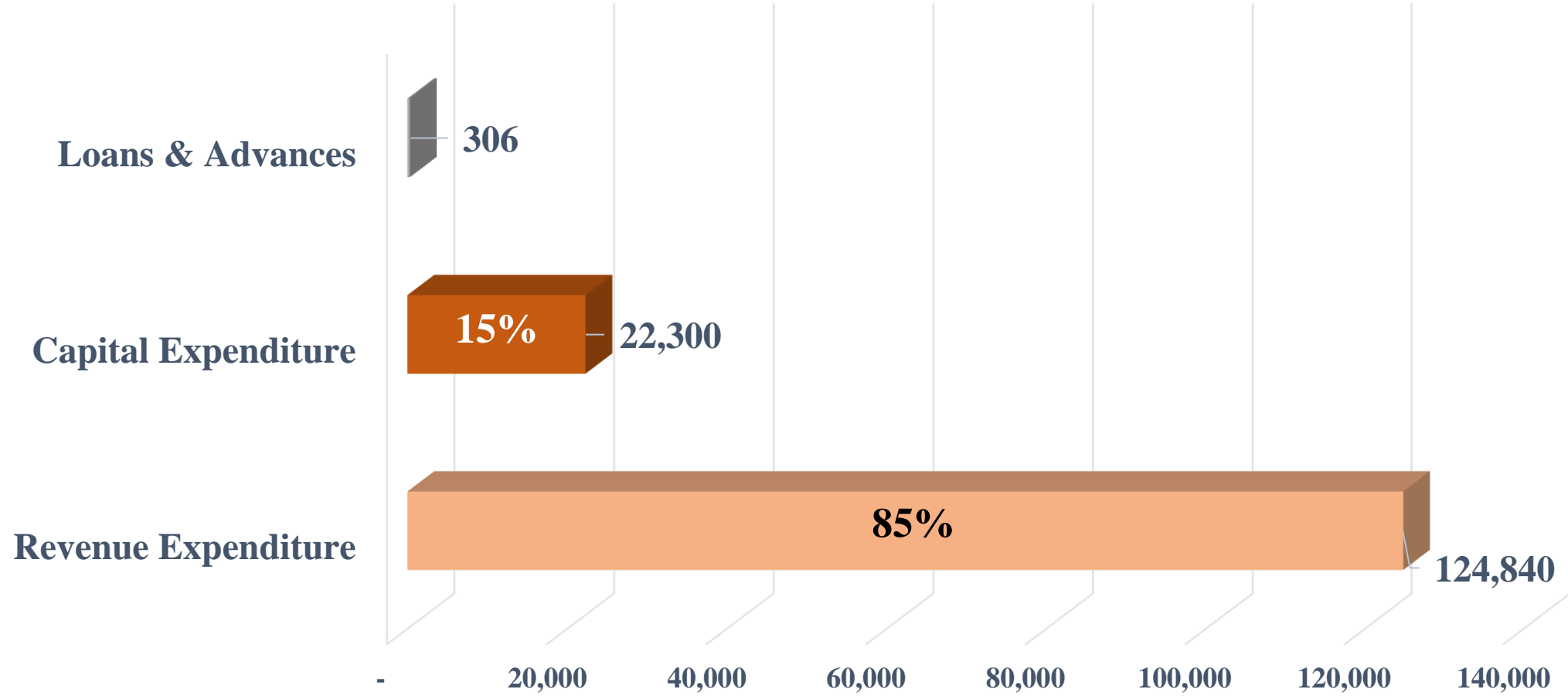
भारत सरकार से स्थानान्तरण
राजस्व प्राप्तियों का 54%





वित्तीय वर्ष 2024 - 25: व्यय

(करोड़ों में)





प्रमुख विभागों के बजट में वृद्धि



क्र.सं.	विभाग का नाम	बजट अनुमान 2023-24	बजट अनुमान 2024-25	वृद्धि मूल्य	वृद्धि %
1.	महिला एवं बाल विकास विभाग	2,675	5,683	3,008	112%
2.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	2,557	5,048	2,491	97%
3.	खनिज साधन विभाग	877	1,580	703	80%
4.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	10,329	17,529	7,200	70%
5.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	5,497	7,552	2,055	37%
6.	कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग	10,070	13,435	3,365	33%
7.	ऊर्जा विभाग	6,665	8,009	1,344	20%
8.	गृह विभाग	6,520	7,570	1,050	16%
9.	नगरीय प्रशासन विकास विभाग	5,360	6,044	684	13%
10.	स्कूल शिक्षा विभाग	19,489	21,489	2,000	10%



प्रमुख विभागों को आवंटन

(करोड़ों में)



स्कूल शिक्षा विभाग

21,489



पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

17,526



कृषि विभाग

13,435



लोक निर्माण विभाग

8,017



ऊर्जा विभाग

8,009



गृह विभाग

7,570



लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

7,552



खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

6,428



नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

6,044



महिला एवं बाल विकास विभाग

5,683



लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

5,047





प्रमुख योजनाएँ

कृषक उन्नति योजना
(रु. 10,000 करोड़)

प्रधानमंत्री आवास
योजना (ग)
(रु. 8,369 करोड़)

जल जीवन मिशन
(रु. 4,500 करोड़)

हायर सेकेंडरी स्कूल
(रु. 3,952 करोड़)

मुख्यमंत्री खाद्यान्न
सहायता योजना
(रु. 3,400 करोड़)

श्री रामलला दर्शन
(रु. 35 करोड़)

5 एचपी कृषि पंपों
के लिए मुफ्त बिजली
(रु. 3,500 करोड़)

महतारी वंदन योजना
(रु. 3,000 करोड़)

शहीद वीर नारायण सिंह
आयुष्मान स्वास्थ्य
योजना
(रु. 1,526 करोड़)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
(रु. 1,820 करोड़)

अमृत मिशन योजना
(रु. 700 करोड़)

इन्वेस्ट छत्तीसगढ़
(रु. 05 करोड़)

दीनदयाल उपाध्याय
भूमिहीन कृषि मजदूर
(रु. 500 करोड़)

राज्य राजधानी क्षेत्र
(एससीआर)
(रु. 5 करोड़)

प्रधानमंत्री ग्राम
सड़क योजना
(रु. 841 करोड़)

शक्ति पीठ
परियोजना
(रु. 5 करोड़)



पंचायत एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (8,369 करोड़)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2,788 करोड़)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (841 करोड़)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (561 करोड़)

ग्राम पंचायत में बिजली भुगतान के लिए अनुदान (500 करोड़)

स्वच्छ भारत मिशन (400 करोड़)

पीएम जन-मन योजना (300 करोड़)

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (94 करोड़)

मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना (50 करोड़)





महिला एवं बाल विकास विभाग

महतारी वंदन योजना (3,000 करोड़)



आंगनबाडी + पूरक पोषण
(700 करोड़)

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
(117 करोड़)



10 नई अम्ब्रेला योजना
(628 करोड़)

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
(38 करोड़)



बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
(8 करोड़)

नोनी सुरक्षा योजना
(25 करोड़)



शिक्षा क्षेत्र

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन



समग्र शिक्षा (1500 करोड़)



पीएम पोषण शक्ति निर्माण (691 करोड़)



160 आईटीआई का उन्नयन (381 करोड़)



औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिपरिया, कबीर धाम



रूसा (94 करोड़)



59 हाई स्कूल और 40 हायर सेकेंडरी स्कूल भवन (100 करोड़)



महतारी दुलार योजना (9 करोड़)



रायपुर वि.वि. में वाणिज्य एवं फोरेन्सिक साइंस



छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान (7.50 करोड़)



आजीविका उत्कृष्टता केंद्र



बस्तर वि.वि. में 20 नवीन शिक्षण विभाग



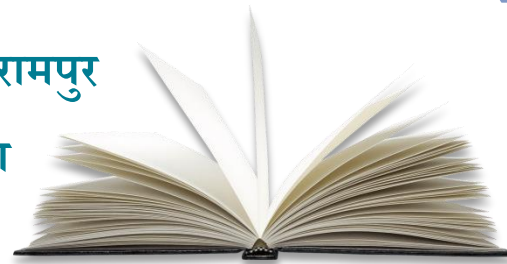
साइंस सिटी (34.90 करोड़)



सूरजपुर, गरियाबंद, कोण्डागांव, सुकमा एवं बलरामपुर
में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना



एस्ट्रो पार्क (2 करोड़)





स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं
शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना
(1,526 करोड़)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (1,821 करोड़)

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (788 करोड़)

जिला स्वास्थ्य केंद्र (788 करोड़)

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (584 करोड़)

मितानिन कल्याण निधि (325 करोड़)

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, अंबिकापुर (50 करोड़)

गरियाबंद, कवर्धा, रायगढ़, मुंगेली, बैकुण्ठपुर, जशपुर एवं नारायणपुर के
जिला चिकित्सालय को आदर्श जिला चिकित्सालय में विकास (20 करोड़)



मेकाहारा का 1200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन
एवं 700 बिस्तर अस्पताल भवन निर्माण (80 करोड़)

05 नवीन जिलों में जिला अस्पताल की स्थापना (20 करोड़)

अस्पतालों का NQAS प्रमाणन (12 करोड़)

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के लिए नया भवन (लागत 700 करोड़)

ट्रामा सेंटर, राजनांदगांव (2.70 करोड़)

मनेन्द्रगढ़ एवं कुनकुरी में 200 बिस्तर अस्पताल



कृषि क्षेत्र

कृषक उन्नति योजना (10,000 करोड़)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (643 करोड़)

एकीकृत बागवानी विकास योजना (205 करोड़)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (200 करोड़)

चिराग योजना (200 करोड़)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (183 करोड़)

कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय का गठन

मधुमक्खी पालन के लिए नई परागण योजना

एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर, जशपुर

नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय, रायगढ़ एवं सूरजपुर

नवीन कृषि महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी-भरतपुर जिला

पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बलरामपुर





खेल एवं युवा कल्याण, पर्यटन क्षेत्र

छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना

ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

खेल अकादमी



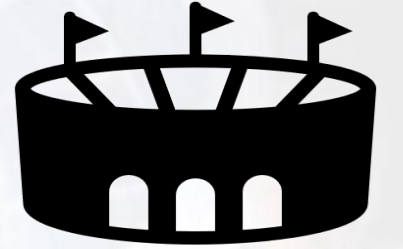
छत्तीसगढ़ युवा रत्न
सम्मान

महिला खेलकूद प्रतियोगिता

मॉडर्न स्पोर्ट्स
स्टेडियम

राज्य युवा महोत्सव

इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम



- ❖ श्री राम लला (अयोध्या धाम) दर्शन
- ❖ शक्ति पीठ परियोजना
- ❖ छत्तीसगढ़ आदिभाषा परिषद का गठन



- ❖ महत्वपूर्ण अभिलेखों का डिजिटलीकरण
- ❖ गोंडी भाषा के प्रोत्साहन हेतु साफ्टवेयर निर्माण
- ❖ मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना



अधोसंरचना क्षेत्र



सीजीआरआईडीसीएल द्वारा सड़कों का निर्माण (1080 करोड़)

1268 नई सड़कों का निर्माण (737 करोड़)

एडीबी सहायता से सड़कों का निर्माण (542 करोड़)

ग्रामीण सड़क कार्यक्रम-चरण 2 (450 करोड़)

केंद्रीय सड़क निधि (300 करोड़)

कटघोरा - डोंगरगढ़ रेलवे लाइन (300 करोड़)

349 पुलों का निर्माण (175 करोड़)

चिरमिरी नागपुर हॉल्ट रेल लाइन (120 करोड़)

18 रेलवे ओवर ब्रिज (27 करोड़)

55 सरकारी गेस्ट हाउस का निर्माण (20 करोड़)

इंडियन रोड कांग्रेस वार्षिक सत्र (4 करोड़)





ऊर्जा क्षेत्र

किसानों को 5 एचपी पंप तक मुफ्त बिजली
(3,500 करोड़)

कृषि पंपों का ऊर्जाकरण
(200 करोड़)

बीपीएल उपभोक्ताओं को एकल बत्ती
कनेक्शन के लिए मुफ्त बिजली
(540 करोड़)

सौर सुजला
(670 करोड़)

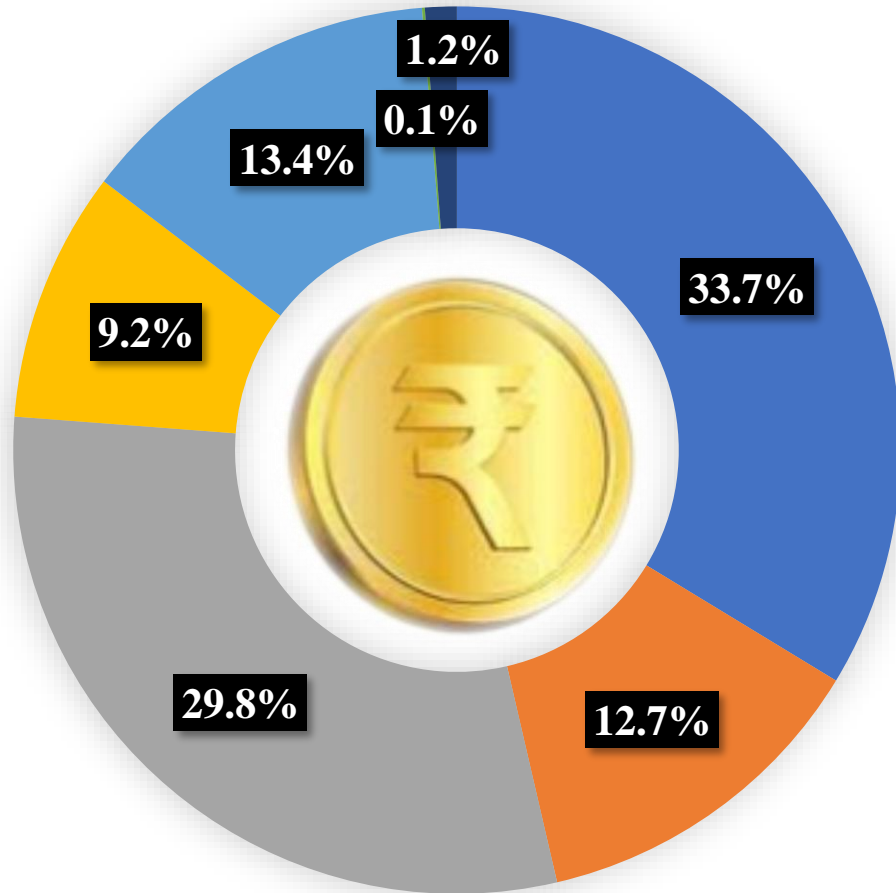
घरेलू उपभोक्ताओं को 50% राहत
(हाफ बिजली बिल)
(1,274 करोड़)

सौर समुदायिक सिंचाई
योजना
(30 करोड़)





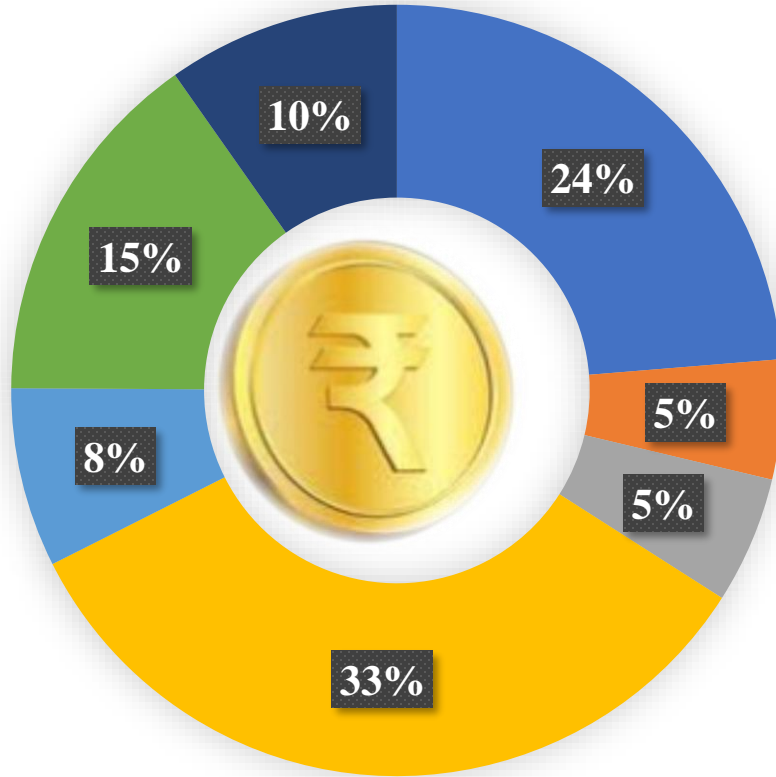
रूपये का आना



- State Own Tax Revenue
 - State Own Non-Tax Revenue
- राज्य का अपना राजस्व (46.4%)
- Share of State in Union Taxes/Duties
 - Grants from Government of India
- भारत सरकार से अन्तरण (39%)
- Net Public Debt
 - Recovery of Loans and Advances
 - Net Public Account Receipts
- पूंजीगत प्राप्तियाँ (14.6%)



रूपये का जाना



- Salaries & Allowances
 - Pension and Retirement Benefits
 - Interest Payments
- } प्रतिबद्ध व्यय (34%)
- Grant-in-Aid
 - Subsidies
- } सहायता एवं सब्सिडी में अनुदान (41%)
- Capital Works & Investments (15%)
 - Others (10%)

धन्यवाद



छत्तीसगढ़ सरकार

छत्तीसगढ़ बजट के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया <https://finance.cg.gov.in> पर जाएं